19 शहरों को जल्द मिलेगी पानी की समस्या से निजात

स्टेट एनुअल एक्शन प्लान में शामिल प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ।

प्रदेश के 19 शहरों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। स्टेट एनुअल प्लान (सैप) के पहले चरण में इन शहरों के बाहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। इस पर करीब 217.36 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इनमें पांच नगर निगम और 14 नगर पंालिका वाले शहर शामिल हैं। योजना को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।

अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) योजना के तहत दी जाने वाली इस सुविधा पर आने वाला खर्च राज्य और केंद्र सरकार मिलकर वहन करेंगे।

पांच नगर निगम व नगर पालिका परिषद वाले 14 शहर शामिल

10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में होने वाले खर्च का एक तिहाई केंद्र देगा। इससे कम आबादी वाले शहरों में दोनों की हिस्सेदारी 50-50 फीसदी होगी। राज्य सरकार 12.5 फीसदी धनराशि सेंटेज चार्ज के रूप में देगी जो रखरखाव पर खर्च होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 'राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति' ने जून में यह योजना केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की 'अपेक्स कमेटी' को भेजी थी। जिसे अब मंजूरी दे दी गई है।

यह काम कराए जाएंगे

उन इलाकों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी जहां अब तक यह सुविधा नहीं थी। पेयजल कनेक्शन न लेने वाले घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। वहीं पुरानी व जर्जर पाइपलाइन को बदला जाएगा। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से नई पाइप लाइन भी डालने का प्रस्ताव है।

इन शहरों में दुरुस्त होगी पेयजलापूर्ति

नगर निगम वाले शहर-इलाहाबाद, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ व अयोध्या। नगर पालिका परिषद वाले शहर- सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, जौनपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, खुर्जा, रामपुर, अमरोहा, हापुड़, बुलंदशहर, शिकोहाबाद, लोनी, संभल व चन्दौसी।

अयोध्या पर होगा विशेष फोकस

फैजाबाद और अयोध्या को मिलाकर नये नगर निगम का गठन कर दिया गया है। यहां की पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने पर विशेष फोकस होगा। जल निगम के एक उच्चाधिकारी का कहना है कि नए शहर के हिसाब से परियोजना में संशोधन भी करना पड़ेगा।